

प्रेषक,

कुणाल शर्मा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1

देहरादून, दिनांक 16 मई 2013

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये सहकारिता विभाग के आयोजनागत पक्ष में जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड कार्यालय के पत्र संख्या:-407/नियो0/जिला योजना/2013-14 दिनांक 22 अप्रैल, 2013 तथा वित्त विभाग के आदेश सं0-284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 एवं आदेश सं0-329/XXVII (1)/2013 दिनांक 15 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में सहकारिता विभाग के लिये आयोजनागत पक्ष में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजना (सामान्य) के सापेक्ष कुल ₹5,69,34,000/-(रुपये पांच करोड़ उनहत्तर लाख चौतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत व्यय हेतु संलग्न विवरणानुसार सम्बन्धित जिलाधिकारियों के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाय। प्रत्येक जनपद में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा संगत योजनाओं के लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही व्यय किया जायेगा।
- (2) सभी कार्यक्रमों की वार्षिक/मासिक लक्ष्यों का निर्धारण धनराशि के आहरण पूर्व तत्काल किया जाय तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों को वित्त, नियोजन विभाग को भी अवगत कराया जाय।
- (3) उक्त धनराशि ऐसे किसी मद/कार्य पर धनराशि व्यय न की जाय जो योजना में स्वीकृत नहीं है, यदि इसका उपयोग अन्यत्र अथवा किसी अलग मद में किया जाता है, तो सम्बन्धित अधिकारी/आहरण एवं वितरण अधिकारी इसके लिये स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- (4) उक्त धनराशि का योजनावार व्यय प्रत्येक माह या अगले माह की 5 तारीख तक बी0एम0-13 पर नियमित रूप से वित्त विभाग एवं शासन तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड को भिजवाना सुनिश्चित करें।
- (5) उक्त व्यय शासन के वर्तमान नियमों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय की उक्त धनराशि को किसी ऐसे कार्य/मद पर व्यय न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुवल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित हो। प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता सम्बन्धी जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित सुसंगत नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।
- (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण सहित शासन/महालेखाकार उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करा दी जाय।
- (7) समितियों को अनुदान/राज सहायता/अंशदान दिये जाने से पूर्व सम्बन्धित नियमों, मानकों/शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

(8) सम्बन्धित जिलाधिकारी का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के कोषागार से आहरण के पूर्व विभागाध्यक्ष तथा शासन को विगत वित्तीय वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए।

- 2- उक्त धनराशि को व्यय किए जाने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं०:- 284/XXVII (1)/2013 दिनांक 30 मार्च, 2013 की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।
- 3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2425-सहकारिता-आयोजनागत-107-क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता, 108-अन्य सहकारी समितियों को सहायता-800-अन्य व्यय (लघुशीर्षक 07, 08, 21) के अन्तर्गत संलग्नक की ग, घ, ङ, च एवं छ की पंक्तियों में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।
- 4- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:-68(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 14 मई, 2013 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(कुणाल शर्मा)  
सचिव।

संख्या:- 735(1)/XIV-1/2013, तददिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त गढ़वाल, / कमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सहायक निबन्धक, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
7. वित्त अनुभाग-4/नियोजन विभाग/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
9. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रमेश कुमार)  
उपसचिव

शासनादेश संख्या-735/XIV-1/13-5(6)/2013 दिनांक 14 मई, 2013 का संलग्नक-  
 वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला योजना (सामान्य) हेतु स्वीकृत बजट के सापेक्ष जनपदों को  
 लेखाशीर्षकवार धनराशियों के आवंटन का विवरण-

(धनराशि हजार रुपये में)

क्रम सं०	जनपद का नाम	योजना का नाम					योग
		2425-सहकारिता आयोजनागत 107-क्रेडिट सहो समितियों को सहायता 91-सहकारी ऋण योजना, 9101-पैक्स के सदस्यों के वेतन हेतु कामन फंडर अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान /राज सहायता	2425-सहकारिता आयोजनागत 108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता 03-सहकारी विभाग की सहकारी उपभोक्ता समितियों को सहायता 20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	2425-सहकारिता आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 07-प्राप्तसहो ऋण समितियों को हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुदान 20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	2425-सहकारिता आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 08-प्राप्त कृषि सहकारी ऋण समितियों को निजी बैंक की स्थापना हेतु प्रबन्धकीय एवं साज-सज्जा अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	2425-सहकारिता आयोजनागत 800-अन्य व्यय, 21-सहकारी कय-विकय योजनान्तर्गत सहो समितियों को वित्तीय सहायता, 20-सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता	
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	
1.	नैनीताल	1288	55	50	100	1550	3023
2.	ऊँसो नगर	0	55	0	0	1284	1339
3.	अल्मोड़ा	6354	125	0	0	1986	8445
4.	बागेश्वर	1753	0	0	0	0	1753
5.	पिथौरागढ़	5092	50	0	20	2500	7662
6.	चम्पावत	2923	10	0	40	400	3373
7.	देहरादून	3503	0	0	200	0	3703
8.	हरिद्वार	0	0	0	0	1300	1300
9.	पौड़ी	6232	0	0	0	700	6932
10.	टिहरी	2717	0	0	300	300	3317
11.	धमोली	3962	0	0	0	0	3962
12.	रूद्रप्रयाग	2801	175	0	120	200	3296
13.	उत्तरकाशी	6749	80	0	200	1800	8829
14.	योग	43354	550	50	980	12000	56934

*Kumar*  
 (कुणाल शर्मा)  
 सचिव 16/5/13